**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2903**
**दिनांक 12 दिसंबर, 2024**

**ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिए भारत की आयात योजनाएं**

**†2903. श्री डी. एम. कथीर आनंद:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) और कमोडिटीज रिसर्च का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड का औसत मूल्य 2024 की अंतिम तिमाही में 80 डॉलर/बीबीएल और 2025 में 75 डॉलर/बीबीएल तथा 2025 के अंत तक घटकर 60 डॉलर प्रति बीबीएल हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी वर्ष में ब्रेंट कच्चे तेल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) स्रोतों के लिए भारत की आयात योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में पेट्रोल/डीजल/एलपीजी/सीएनजी/एलएनजी की कीमतों को कम करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए गए हैं/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा तेल के अत्यधिक आयात के कारण उत्पन्न भारी बोझ को कम करने के लिए कोई नवीन उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) और (ख): अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का मूल्य मांग आपूर्ति परिदृश्य, भू-राजनैतिक मुद्दों तथा विभिन्न अन्य बाजार दशाओं पर आधारित है। कच्चे तेल के मूल्यों के बारे में, विशेषरूप से चल रही अस्थिरता के दौरान बिल्कुल सही पूर्वानुमान कर पाना मुश्किल कार्य है। भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांशत: कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण तथा वार्षिक आवधिक संविदाओं और साथ ही अल्पकालिक हाजिर संविदाओं के माध्यम से कच्चे तेल के विभिन्न आपूर्ति स्रोतों के मूल्यांकन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं को वार्षिक आधार पर अंतिम रूप प्रदान करती हैं। ओएमसीज तथा स्टैंडएलोन रिफाइनरियों द्वारा आवधिक और हाजिर संविदाओं के माध्यम से कच्चे तेल की इस अधिप्राप्ति के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कच्चे तेल की विभिन्न अनुकूल श्रेणियों (ब्रैंट/डब्ल्यूटीआई के लिए बैंचमार्क किए गए कच्चे तेल सहित) के लिए संविदा की गई है।

**(ग): पेट्रोल और डीजल**

घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान करने सहित सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य घटकर क्रमश: 94.77 रुपए प्रति लीटर और 87.67 रुपए प्रति लीटर, (दिल्ली में मूल्य) हो गए। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट दरों को कम कर दिया था। मार्च, 2024 में ओएमसीज ने भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी।

भारत सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

हाल ही में, पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रुप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पोओएल) डिपो से दूर, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को भी कम कर दिया है।

**एलपीजी:**

भारत घरेलू एलपीजी के खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। सरकार उपभोक्ता हेतु घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। जबकि औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 64 प्रतिशत (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से नवंबर 2024 में यूएस अमेरीकी डॉलर 632 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई, दूसरी ओर प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 44 प्रतिशत (अगस्त 2023 में 903 रूपए से नवम्बर, 2024 में 503 रुपए तक) तक कमी हुई थी।

वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य दिल्ली में 803 रुपए है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवा रही है। यह पूरे देश में 10.33 करोड़ से भी अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं को बैंक खातों में सीधे राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया गया है, ताकि उच्च अन्तरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पर न डालने के कारण उन्हें हुई अल्प वसूली की भरपाई की जा सके।

**प्राकृतिक गैस**

किसी भी स्थल पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मूल्यों का निर्धारण प्राधिकृत नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनी द्वारा अधिप्राप्त गैस की लागत, राज्य करों, प्रशुल्क तथा अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) का आयात विभिन्न प्राकृतिक गैस उपभोक्ताओं, विपणनकर्ताओं आदि द्वारा दीर्घकालिक संविदाओं के आधार पर और हाजिर बाजारों में किया जाता है। एलएनजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रेता और विक्रेता के बीच वाणिज्यिक सहमति से तय होते हैं। तथापि, भारत में सीएनजी मूल्यों पर अंतरराष्ट्रीय गैस मूल्यों में होने वाली वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2013-14 में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) को घरेलू एपीएम गैस आवंटन में लगभग 250% की वृद्धि करने, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विद्युत तथा अन्य गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस का विपथन करने और घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन के लिए सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र को पहली प्राथमिकता के रूप में घोषित करने सहित अनेक कदम उठाए हैं।

(घ): सरकार ने कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देशभर में प्राकृतिक गैस को ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा देना जिससे अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस के हिस्से को बढ़ाया जा सके तथा गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सके, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी एथेनॉल, संपीडित जैव गैस और जैवडीजल जैसे नवीनीकरणीय तथा वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, विभिन्न नीति पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल की शुरुआत भी की गई है।

तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. हाइड्रोकार्बन खोजों, 2014 के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत छूटों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लिए नीति
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016
iv. पीएससीज की अवधि बढ़ाए जाने के लिए नीति, 2016 और 2017
v. कोल बेड मिथेन के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए नीति, 2017
vi. नेशनल डेटा रिपोज़िटरी, 2017 की स्थापना
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन, 2017
viii. पूर्व-नवीन अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति (पूर्व-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससीज के विस्तार के लिए नीति ढांचा।

ix. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीति, 2018

x. मौजूदा उत्पादन साझेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं तथा नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण तथा शोषण के लिए नीति ढांचा

xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020

xii. ओएएलपी ब्लॉक में चरण-I के तहत नीलामी में बोलीदाता को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिनों में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व साझेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) तथा नो ड्रिलिंग प्रतिबद्धता

xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग कि.मी. 'नो-गो' क्षेत्र को प्रतिबंध से मुक्त करना जो दशकों से अन्वेषण के लिए बंद था।

xiv. सरकार भी ऑनलैंड और अभितटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा अधिग्रहण तथा स्ट्रैटीग्राफिक कूपों के वेधन के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि भारतीय तलछटी बेसिनों के गुणवत्ता डेटा को बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के बाहर 20,000 एलकेएम ऑनलैंड और 30,000 एलकेएम अभितटीय 2डी भूकंपीय डेटा के अतिरिक्त अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

*******